



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 10 दिसम्बर, 2003/19 अग्रहायण, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 नवम्बर, 2003

संख्या एफडीएस-ए(3)-3/94—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्तुतक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तोल और माप संगठन में उप-नियन्त्रक, विधिक मापविज्ञान (तोल एवं माप) (वर्ग-I, राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप-नियन्त्रक, विधिक मापविज्ञान (तोल एवं माप) (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) अधिसूचना संख्या एफडीएस-ए(3)-10/81, तारीख 17 सितम्बर, 1981 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित दी हिमाचल प्रदेश फूड एण्ड सप्लायज डिपार्टमेंट डिप्टी कन्ट्रोलर (वेट एण्ड मईयर) (क्लास-II, गजेटिड) रिक्रूटमेंट एण्ड प्रमोशन रूलब, 1981 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है। जहां तक ये उप नियन्त्रक, विधिक मापविज्ञान (तोल एवं माप) (वर्ग-I, राजपत्रित) के पद से सम्बन्धित है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई उपरोक्त नियम-2(1) के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

बी० एस० चौहान,
प्रधान सचिव।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) उप-नियन्त्रक, विधिक माप-विज्ञान (तोल एवं माप) (वर्ग-I, राजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

- | | |
|--|--|
| 1. पद का नाम | उप नियन्त्रक, विधिक मापविज्ञान (तोल एवं माप) |
| 2. पदों की संख्या | 1 (एक) |
| 3. वर्गीकरण | वर्ग-I (राजपत्रित) |
| 4. वेतनमान | स्लैब 7220-220-8100-275-10300-340-11660। |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद | चयन पद |
| 6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु। | 18 से 45 वर्ष : |

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं/किये गये थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद(पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधि-गृहीत किया जाता है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ।
- (ii) अखिल भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से, बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स (पाठ्यक्रम) सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो ।
- (iii) सोल और माप में कम से कम 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो ।

वैकल्पिक अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीति-रिवाजों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं ?

आयु : लागू नहीं ।
शैक्षणिक अर्हताएं : लागू है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता ।

शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।

सहायक नियन्त्रकों में से, जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा-विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाते के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यदि कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, इनमें से जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझ जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तु. के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ गणना व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्स परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नान-टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे ऐक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त यथानिर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना?

विभागीय प्रोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों

के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा

सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी अनिवार्य होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this department notification No. FDS-A (3)-3/94, dated 22-11-2003 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd November, 2003


No. FDS-A (3)-3/94.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Controller, Legal Metrology (Weights and Measures) (Class-I, Gazetted) in the Weights and Measures Organisation of H.P. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Deputy Controller, Legal Metrology (Weights and Measures), (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Food and Supplies Department Deputy Controller(W&M), Class-II Recruitment & Promotion Rules, 1981 notified *vide* Notification No. FDS-A(3)10/81 dated 17th September, 1981 and as amended from time to time are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Deputy Controller, Legal Metrology (Weights & Measures) (Class-I, Gazetted).

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under Rule 2(1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order, 

B. S. CHAUHAN,
Principal Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY CONTROLLER, LEGAL METROLOGY (WEIGHTS AND MEASURES) (CLASS-I, GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS HIMACHAL PRADESH

- | | |
|--|---|
| 1. Name of the post | Deputy Controller, Legal Metrology
(Weights and Measures). |
| 2. Number of post(s) | 1 (One) |
| 3. Classification | Class-I (Gazetted) |
| 4. Scale of pay | Rs. 7220-220-8100-275-10300-340-11660. |
| 5. Whether selection post or non-selection post? | Selection |
| 6. Age for direct recruitment | Between 18 and 45 years: |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous

Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).

Essential Qualification:

- (i) A graduate from a recognised University or its equivalent.
- (ii) Successfully completion of basic training course from All India Institute of Legal Metrology, Ranchi or any other recognised Institute.
- (iii) Atleast 7 years administrative experience in Weights and Measures.

Desirable Qualifications:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s)?

Age : Not applicable.

Educational Qualifications: Yes applicable.

9. Period of probation, if any

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.

100% by promotion failing which by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst the Assistant Controller with three years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade.

- (1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services)

Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

- (2) Similarly in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules :

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service as referred to above shall remain unchanged.

DPC to be presided over by the Chairman, H.P.P.S.C or a member thereof to be nominated by him.

As required under the law

A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other Recruiting Authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/Other Recruiting Authority, as the case may be.

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in H. P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of persons or post(s).

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.

16. Reservation

17. Departmental Examination

18. Powers to relax